



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्रहायण 9, 1940

No. 849]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRAHAYANA 9, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सं. 1/2018-सेवा कर

सा.का.नि. 1156(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी प्रथा के अनुसार, जो साधारणतया प्रचलित थी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 3 की उपधारा (7) में यथा परिभाषित “स्थानीय प्राधिकारियों” द्वारा “मार्गाधिकार” के रूप में दी गई सेवाओं पर सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था और यह सेवा उक्त अवधि में ऐसे सेवा कर के लिए दायी थी, जो उक्त प्रथा के अनुसार संदत्त नहीं किया जा रहा था।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के प्रवृत्त होने से पहले की गई या लोप की गई बातों के संबंध में यह निदेश देती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 की उपधारा (7) में यथा परिभाषित “स्थानीय प्राधिकारियों” द्वारा उक्त अवधि में, उक्त प्रथा के कारण “मार्गाधिकार” के रूप में दी गई सेवाओं पर, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अधीन संदेय सेवा कर संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

[फा. सं. 137/12/2018-सेवा कर]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2018

No. 1/2018-Service Tax

G.S.R. 1156(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the 1st day of July, 2012 and ending with the 30th day of June, 2017 (hereinafter referred to as the said period), according to a practice that was generally prevalent, there was non-levy of service tax, on the services by way of granting of “right of way” by “local authorities”, as defined in sub-section (7) of section 3 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), and this service was liable to service tax, in the said period, which was not being paid according to the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and clause (e) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 (12 of 2017), in respect of things done or omitted to be done before the coming into force of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby directs that the service tax payable under section 66B of the Finance Act, 1994, on the services by way of granting of “right of way” by “local authorities”, as defined in sub section (7) of section 3 of the Indian Telegraph Act, 1885, in the said period, but for the said practice, shall not be required to be paid.

[F. No. 137/12/2018-Service Tax]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.